

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

30

समाज कल्याण अनुभाग-01.

देहरादून, जुलाई 2009.

विषय : जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत विकास खण्ड-कालसी, जनपद-देहरादून में मीनस अटाल मोटर मार्ग को यातायात योग्य बनाने हेतु धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-353-54/ज.जा.क./ज.उ.यो./2007-08, दिनांक 24 मई 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत विकास खण्ड-कालसी, जनपद-देहरादून में स्थित मीनस अटाल मोटर मार्ग को 19 से 23 किमी तक यातायात योग्य बनाने हेतु लोक निर्माण विभाग, सहिया (कालसी), देहरादून द्वारा उपलब्ध कराए गए आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त रुपये 1,00,96,000/- (रुपये एक करोड़ छियानवे हजार मात्र) की धनराशि पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए 1.00 करोड़ रुपया वित्तीय वर्ष 2007-08 में उक्त मार्ग हेतु आरक्षित धनराशि से तथा अवशेष धनराशि रुपये 96 हजार चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि से इस प्रकार कुल रुपये 1,00,96,000/- (रुपये एक करोड़ छियानवे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. उक्त कार्य के सम्बन्ध में, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/08 दिनांक 15.12.08 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं कार्य को निर्धारित समय सारणी के अनुसार अवश्य पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें "शिड्यूल ऑफ रेट" में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाए।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितने कि स्वीकृत मानक हैं, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग और "MORTH" द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
6. उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु धनराशि व्यय किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य कार्यदायी संस्था/विभाग द्वारा धनराशि उपलब्ध न कराई गई हो।
7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भू-मांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।
8. आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उन्हीं मदों पर किया जाए। एक मद की धनराशि दूसरी मदों में कदापि व्यय न की जाए।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में परीक्षण करा लिया जाए तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।
10. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किए जाएंगे। विलम्ब के कारण यदि आगणन का पुनरीक्षण किया जाता है तो उसे अपने निजी स्रोतों से वहन करेंगे। स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए।
11. स्वीकृत धनराशि का व्यय बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
12. कार्य कराते समय निविदा विषयक नियमों एवं मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।
13. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
14. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए तथा कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।
15. शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
16. अप्रयुक्त धनराशि को निर्धारित समयान्तर्गत नियमानुसार राजकोष में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
18. इस सम्बन्ध में होने वाले कुल व्यय रुपये 1,96,00,000/- में से रुपये 1,00,00,000/- की धनराशि शासनादेश संख्या-673/XVII(1)/07-42(प्रकोष्ठ)/2007, दिनांक 19 नवम्बर 2007 द्वारा जनपद-देहरादून को उपलब्ध कराई गई धनराशि में से अवशेष बची धनराशि से व्यय की जाएगी। शेष रुपये 96,000/- की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के लेखानुदान की "अनुदान संख्या-31" के "आयोजनागत पक्ष" के लेखाशीर्षक "4225-अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-800-अन्य व्यय-03-अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास" की मानक मद "24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाली जाएगी।
19. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- 233 (P)/XXVII-3/2009-10, दिनांक 02 जून 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय;

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 794 (1)/XVII-1/2009-11(13)/2008, तददिनांक :
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. अधिशासी अभियन्ता, अ.ख., लोक निर्माण विभाग, सहिया (कालसी), जनपद-देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से
(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।